शरत बाबू दिगुमार्टी

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(आपराधिक अपील संख्या 1222/2016)

14 दिसंबर 2016

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जे जे,]

दंड संहिता, 1860: धारा 292 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री से संबंधित अपराध - अपीलकर्ता के विरुद्ध आईटी अधिनियम की धारा 67 की कार्यवाही हटा दी गई, लेकिन कार्यवाही धारा 292 नहीं हटाई गई - उच्च न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि धारा 292 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाने वाली पर्याप्त सामग्री थी - क्या अपीलकर्ता जिसे आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया है, उस पर धारा 292 के तहत कार्रवाई की जा सकती है - माना गया: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अश्लीलता आईटी अधिनियम की योजना के अंतर्गत आती है - आईटी अधिनियम एक विशेष कानून है - विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होगा - इसलिए, अतिव्यापी प्रभाव वाले विशेष प्रावधान एक आपराधिक कृत्य और अपराधी को कवर करते हैं, और तत्काल मामले में अपीलकर्ता धारा 292 के दायरे से बाहर हो जाएगा - अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई - अश्लील किताबें और चित्र अधिनियम, 1856 - अश्लील प्रकाशन अधिनियम, 1925 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - एसएस.2(1)(टी), 67 ए, 678, 69, 79,81

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

1. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि सामग्री का कथित कब्ज़ा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का गठन करता है जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 2 (एल) (टी) के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 67 ए इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 67 बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 69 किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसा कि इसमें कहा गया है, इसमें एक दंडात्मक पहलू भी शामिल है, जो ग्राहक या मध्यस्थ उप-धारा (3) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 67 में स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने, प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 67 ए और 67 बी के साथ पढ़ा जाने वाला उक्त प्रावधान आईटी अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों से संबंधित एक पूर्ण कोड है। धारा 79 व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक छूट प्रावधान है। धारा 81 यह भी विशेष रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। यदि कथित अपराध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अपराध से संबंधित है, तो सभी प्रावधानों का अपना महत्व और महत्व होगा। आईटी एक्ट एक विशेष अधिनियम है। इसमें विशेष प्रावधान हैं. आईपीसी की धारा 292 अश्लील किताबों आदि की बिक्री को अपराध बनाती है, लेकिन एक बार जब अपराध का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ संबंध

या संबंध हो जाता है तो धारा 79 आईटी अधिनियम के संरक्षण और प्रभाव को नजरअंदाज या नकारा नहीं जा सकता है। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है और. अधिनियम को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके और विधायी मंशा के अनुरूप बनाया जा सके। आईटी अधिनियम की धारा 81 के पीछे यही आदेश है। आईटी अधिनियम द्वारा दी गई अतिरिक्त सुरक्षा लागू होगी। [पैरा 18, 24, 25, 28)(1027-डी; 1031- ए-बी; 1032-सी-डी; 1034-एफ-एच; 1036-ए-बी)

अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (2008) 13 एससीसी 703; रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1965 एससी 881: 1965 एससीआर 65; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: 2015 (5) एससीआर 963 - पर भरोसा किया गया।

2. एक बार जब अधिभावी प्रभाव वाले विशेष प्रावधान किसी आपराधिक कृत्य और अपराधी को कवर कर लेते हैं, तो वह आईपीसी के दायरे से बाहर हो जाता है और इस मामले में, धारा 292। ट्रांसमिशन के इलेक्ट्रॉनिक रूप आईटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो एक विशेष कानून है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि एक विशेष कानून सामान्य और पूर्व कानूनों पर हावी होगा। जब अधिनियम विभिन्न प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता से संबंधित है, तो यह आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध को कवर करता है। उच्च न्यायालय इस भूल में पड़ गया कि यद्यपि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप नहीं लगाया गया है, फिर भी अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। [पैरा 32,34)(1037-एफ-जी; 1038-एफ-जी]

सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2001) 3 एससीसी 71:2001 (1) एससीआर 932; जीवन कुमार राऊत बनाम सीबीआई (2009) 7 एससीसी 526:2009 (10) एससीआर 272 - पर भरोसा किया गया।

पी. विजयन बनाम केरा/ए और एएम राज्य: (2010) 2 एससीसी 398: 2010 (2) एससीआर 78; अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्य। (2012) 9 सेकंड 460: 2012 (7) एससीआर 988; कामेश्वर प्रसाद राज्य क्यूएफ बिहार 1962 सप. (3) एससीआर 369; सेंट्रल जेल बनाम राम मनोहर लोहिया एआईआर 1960 एससी 633: 1960 एससीआर 821; देवीदास रामचन्द्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2015) 6 एससीसी 1:2015 (7) एससीआर 853; सरवन सिंह और अन्य. वी. कस्तूरी लाल (1977) 1 एससीसी 750 : 1977 (2) एससीआर 421; तालचेर नगर पालिका बनाम तालचेर विनियमित बाजार समिति (2004) 6 एससीसी 178: 2004 (3) सप्ल.एससीआर 167 - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2008) 13 धारा 703	निर्भर	पैरा 3
2010 (2) एससीआर 78	संदर्भित	पैरा 9
2012 (7) एससीआर 988	संदर्भित	पैरा 9
1965 एससीआर 65	निर्भर	पैरा 15
2015 (5) एससीआर 963	निर्भर	पैरा 19
1962 सप्ल.(3) एससीआर 369	संदर्भित	पैरा 20

1960 एससीआर 821	संदर्भित	पैरा 20
2015 (7) एससीआर 853	संदर्भित	पैरा 22
1977 (2) एससीआर 421	संदर्भित	पैरा 28
2004 (3) सप्ल.एससीआर 167	संदर्भित	पैरा 29
2001 (1) एससीआर 932	निर्भर	पैरा 31
2009 (10) एससीआर 272	निर्भर	पैरा 33

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1222/2016

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 127/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 31.08.2015 से।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर विज्ञापन बनाम, आर. एन. करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, करण देव चोपड़ा, सुश्री श्रद्धा करोल, अभिनव सेखरी, नितिन सलूजा, सुश्री आकांक्षा मुंजाल, मिलिंदा शन्ना, साईकृष्ण राजगोपाला, सुश्री .जूलियन जॉर्ज, धाविश चितकारा, विजा:आईओ: सौंधी, सलीम मसान, मैसर्स करंजवाला एंड कंपनी, अपीलकर्ता के लिए सलाहकार।

ए.के. सांघी, आर.के. राठौड़, वरिष्ठ वकील, सुश्री माधवी दीवान, अभिषेक अत्रे, डी.एस. माहरा, सुश्री निधि खन्ना, प्रतिवादी के लिए वकील।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई.

2. अपीलकर्ता अवनीश बजाज और अन्य के साथ एफआईआर संख्या 645/2004 में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद, विद्वान

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने 14.02.2006 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292 और 294 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया और उन सभी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 (संक्षेप में, "आईटी अधिनियम")। अवनीश बजाज ने कई आधारों पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध मामला संख्या 3066/2006 दायर किया, जो 29.05.2008 के आदेश के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रथम दृष्टया मामला आईपीसी की धारा 292 के तहत बनता है, लेकिन इसने राय व्यक्त की कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता अवनीश बजाज आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं थे और तदनुसार, उन्हें आईपीसी की धारा 292 और 294 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया। तथापि, प्रथम दृष्टया उसे आईटी अधिनियम की धारा 85 के साथ पठित धारा 67 के तहत अपराध करते हुए पाया गया और ट्रायल कोर्ट को उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आरोप के आदेश पारित करने के अगले चरण पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

3. उपरोक्त आदेश से दुखी होकर, अवनीश बजाज ने 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1483 को प्राथमिकता दी। उक्त अपील को ईबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1484/2009) के साथ टैग किया गया था। उक्त अपीलों पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, "एनआई अधिनियम") की धारा 138 और 141 की व्याख्या से संबंधित अन्य अपीलों के साथ तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई थी कि अनीता हाडा बनाम गॉडजटलियर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड1 में दो विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था।

4. अवनीश बजाज द्वारा उठाई गई दलीलों और एनआई अधिनियम के संदर्भ में उठे मुद्दे की समानता के संबंध में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार के लिए उभरे विवाद को इस प्रकार बताया: -

> "2. आपराधिक अपील संख्या 1483 और 1484/2009 में, शामिल मुद्दा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में "2000 अधिनियम") की धारा 85 की व्याख्या से संबंधित है, जो अधिनियम की धारा 141 के अनुरूप है। विदित हो कि अपीलकर्ता कंपनी के एक निदेशक पर दंड संहिता, 1860 की धारा 292 और 2000 अधिनियम की धारा 67 के तहत कंपनी को आरोपी बनाए बिना मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन की शुरूआत को उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता कंपनी के साथ-साथ निदेशकों के खिलाफ धारा 67 के तहत 2000 अधिनियम की धारा 85 के साथ अपराध बनता है और, उक्त आधार पर कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
>
> 3. इन दो अपीलों में जो मुख्य मुद्दा उभरा है वह यह है कि क्या कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल किए बिना अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता था और क्या कंपनी को आरोपी बनाए बिना उपरोक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निदेशकों पर मुकदमा चलाया जा सकता था।"

5. एनआई अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में, न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया: -

> "58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करना,
>
> हमारी सुविचारित राय है कि कंपनी द्वारा अपराध करना दूसरों की परोक्ष देनदारी को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त है। इस प्रकार, अनुभाग में दिखाई देने वाले शब्द "साथ ही साथ कंपनी" यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति ही याचिका में दिए गए कथनों और उसके सबूतों के अधीन अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। इस तथ्य से कोई भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। यदि इसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो इससे इसकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब किसी निदेशक को दोषी ठहराए जाने पर कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रभावित हो।"

6. जहां तक अवनीश बजाज की अपील का सवाल है, कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 85 का हवाला दिया जो इस प्रकार है:-

> "85. कंपनियों द्वारा अपराध.-(1) जहां इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय

के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था, उल्लंघन का दोषी होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

(2) उप-धारा {1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, जैसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।"

7. उसी की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:-

"64.उपरोक्त प्रावधान की संरचना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 141 से संबंधित हमारा विश्लेषण पूरी तरह से 2000 के अधिनियम पर लागू होगा। इस प्रकार निर्णय दिया गया, निदेशक को 2000 अधिनियम की धारा 85 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी

नहीं ठहराया जा सकता था। परिणामस्वरूप, 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1483 की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। जहां तक कंपनी का सवाल है, उसे आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया था। एर्गो, मौजूदा अवतार में शुरू की गई कार्यवाही न तो कंपनी के खिलाफ और न ही निदेशक के खिलाफ चलने योग्य है। तार्किक अनुक्रम के रूप में, अपील की अनुमति दी जाती है और अवनीश बजाज के साथ-साथ कंपनी के खिलाफ वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।"

8. फैसला सुनाए जाने के बाद, वर्तमान अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ कार्यवाही बंद करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही बंद कर दी। हालाँकि, आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्यवाही नहीं हटाई गई और 22.12.2014 के आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 292 के तहत आरोप तय किए।

9. आरोप तय करने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 127/2015 में उच्च न्यायालय का रुख किया और आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि आईपीसी की धारा 292 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसकी संलिप्तता दिखाने वाली पर्याप्त सामग्री है। इसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और अपीलकर्ता की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है

और उसके बाद पी. विजयन बनाम केरा/ए और अन्य राज्य 1 और अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्य की घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। •' जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत आरोप तय करने की औचित्य से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग से संबंधित है।

10. विचार के लिए जो केंद्रीय मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता जिसे आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया है, उस पर आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

11. ज्ञात हो, सुनवाई की पहली तारीख पर, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए.एम.सिंघवी ने आग्रह किया कि उठाए गए विवाद में आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है और इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने भारत संघ के विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुनना उचित समझा। सुनवाई के दौरान, न्यायालय को भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार और भारत संघ के विद्वान वकील श्री आर.के.राठौर द्वारा सहायता प्रदान की गई।

12. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता मध्यस्थ का वरिष्ठ प्रबंधक है और मध्यस्थ के प्रबंध निदेशक को अनिता हाडा (सुप्रा) और आगे के निर्णय के अनुसार सभी अपराधों से मुक्त कर दिया गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ जो एकमात्र आरोप लगाया गया है वह आईपीसी की धारा 292 के संबंध में है। डॉ. सिंघवी का कहना है कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त किए जाने के बाद अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री रोहतगी ने न्यायालय की सहायता करते हुए कहा कि आईटी अधिनियम की

धारा 67 एक विशेष प्रावधान है और यह आईपीसी की धारा 292 को खत्म कर देगी। उन्होंने इंटरनेट पर संदर्भित अपराधों और प्रिंट/पारंपरिक मीडिया या आईपीसी की धारा 292 में व्यक्त अपराधों के बीच अंतर किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी.एस. महरा बहस करेंगे कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत निर्धारित किसी भी अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने को आईपीसी की धारा 292 के तहत दी गई अश्लील सामग्री की बिक्री के साथ भ्रमित या बराबर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अपराध पूरी तरह से अलग हैं। उनका आग्रह है कि किसी आरोपी पर आईपीसी की धारा 292 के तहत स्वतंत्र रूप से अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही उसे आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत बरी कर दिया गया हो। उनके अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 67 से मुक्ति के बाद धारा 292 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप लगाने और मुकदमा चलाने पर कानून में कोई रोक नहीं है। विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि मध्यस्थ के प्रभारी व्यक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अश्लील सामग्री की बिक्री से संबंधित है जो आईपीसी की धारा 292 के तहत दंडनीय है न कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत। विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई दलील तकनीकी के दायरे में है और उस आधार पर, आरोप के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

13. डॉ. सिंघवी ने हमें भारत में अश्लीलता के निषेध के विधायी इतिहास से अवगत कराया। उन्होंने अश्लील पुस्तकें और चित्र अधिनियम, 1856 का उल्लेख किया है। उक्त अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य अश्लील पुस्तकों और चित्रों की बिक्री या प्रदर्शन को रोकना था। इसमें दूसरों को परेशान करने वाले अश्लील गाने आदि गाने पर रोक लगा दी गई। उक्त गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को

100/- रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की कैद या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। विदित हो कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने अश्लील प्रकाशन अधिनियम, 1925 का भी उल्लेख किया है। उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है।

14. आईपीसी की धारा 292 अपने मूल रूप में इस प्रकार पढ़ी जाएगी:"

292. अश्लील किताबों आदि की बिक्री आदि - जो कोई (ए) बेचता है, किराये पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाता है, या बिक्री, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या संचलन के प्रयोजनों के लिए, कोई अश्लील पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या कोई भी अन्य अश्लील वस्तु बनाता है, उत्पादित करता है या अपने कब्जे में रखता है, या

(बी) उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण करता है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाई जाएगी, या

(सी) किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है, जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तुएं उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए बनाई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयात, निर्यात, संप्रेषित,

सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाई गई हैं, या

(डी) विज्ञापन देता है या किसी भी माध्यम से यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, या

(ई) किसी ऐसे कार्य को करने की पेशकश या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है, तो उसे तीन महीने तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपवाद.-यह धारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक रूप से रखी या उपयोग की जाने वाली किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग या पेंटिंग या किसी भी मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रतिनिधित्व पर लागू नहीं होती है। किसी भी मंदिर में, या किसी भी कार पर, जिसका उपयोग मूर्तियों के परिवहन के लिए किया जाता है, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखा या उपयोग किया जाता है।"

15. आईपीसी की धारा 292 की संवैधानिक वैधता को रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य में चुनौती दी गई थी। संवैधानिक वैधता पर हमला करते हुए, संविधान पीठ के समक्ष यह आग्रह किया गया कि उक्त प्रावधान संविधान की धारा 19 (एल) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंगत और अस्वीकार्य प्रतिबंध लगाता है। संविधान पीठ की राय इस प्रकार है:-

"7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह मौजूदा कानूनों के पक्ष में एक अपवाद भी बनाता है जो सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता के हित में अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। विवादग्रस्त दंड संहिता की धारा 1923 में जिनेवा में भारत द्वारा हस्ताक्षरित अश्लील प्रकाशनों के दमन या तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 को प्रभावी बनाने के लिए अश्लील प्रकाशन अधिनियम (7/1925) द्वारा पेश की गई थी। यह अश्लीलता से आगे नहीं जाता है जो सीधे लेख के दूसरे खंड के "सार्वजनिक शालीनता (1) (1868) एल.आर. 3 क्यू.बी. 360. और नैतिकता" शब्दों के अंतर्गत आता है। शब्द, जैसा कि शब्दकोश हमें बताते हैं, अश्लील होने की गुणवत्ता को दर्शाता है जिसका अर्थ है विनम्रता या शालीनता के लिए अपमानजनक; भद्दा, गंदा और घृणित। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अश्लीलता को दबाना समाज का अहम हित है। निःसंदेह, अश्लीलता और अश्लीलता के बीच कुछ अंतर है कि अश्लीलता में यौन इच्छा जगाने के इरादे से लिखे गए लेख, चित्र आदि शामिल होते हैं, जबकि अश्लीलता में ऐसे लेखन आदि शामिल हो सकते हैं, जिनका इरादा ऐसा करने का नहीं होता, लेकिन जिनमें ऐसी प्रवृत्ति होती है। बेशक, दोनों ही सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पोर्नोग्राफ़ी अधिक गंभीर रूप में अश्लीलता है। श्री गर्ग जानबूझकर अश्लीलता के मामलों तक कार्रवाई को सीमित करना चाहते हैं, जिसे वे "गंदगी के लिए गंदगी" के रूप में

वर्णित करते हैं और जिसे अब हार्ड-कोर पोर्नोग्राफ़ी की उपाधि मिली है, जिसके अंतर्गत इस शब्द का अर्थ उच्च कामुक प्रभाव वाले कामेच्छापूर्ण लेखन से है, जिसे किसी साहित्यिक या कलात्मक चीज़ से नहीं बचाया जा सकता है। और यौन भावनाओं को जगाने का इरादा है।

X X X X X X

9. पहला उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि यह उत्सर्जन कार्यों से संबंधित था और दूसरा इसलिए क्योंकि यह यौन दमन से संबंधित था। (सेक्स, साहित्य और सेंसरशिप पृष्ठ 26 201 देखें)। अश्लीलता की निंदा व्यक्ति के साथ-साथ लोगों की नैतिकता पर भी निर्भर करती है। यह हमेशा डिग्री का प्रश्न होता है या जैसा कि वकील कहने के आदी हैं, कि रेखा कहाँ खींची जानी है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि अश्लीलता अपने आप में "सार्वजनिक हित या लाभ के विचारों, राय और सूचना के प्रचार-प्रसार में बेहद खराब मूल्य है।" जब सार्वजनिक हित या लाभ के विचारों, राय और जानकारी का प्रचार होता है, तो समस्या का दृष्टिकोण अलग हो सकता है क्योंकि तब समाज का हित स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के पक्ष में तराजू को झुका सकता है। इस प्रकार, चिकित्सा विज्ञान पर अंतरंग चित्रण और तस्वीरों वाली किताबें, हालांकि एक अर्थ में अनैतिक हैं, अश्लील नहीं मानी जाती हैं, लेकिन चिकित्सा पाठ के बिना पुस्तक के रूप में एकत्र किए गए वही चित्र और तस्वीरें निश्चित रूप से अश्लील मानी जाएंगी। धारा, भारतीय दंड संहिता इस अर्थ में अश्लीलता से संबंधित है और इस

प्रकार कला के दूसरे खंड के मद्देनजर इसे अमान्य नहीं कहा जा सकता है।"

16. अंततः, न्यायालय ने उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। संविधान पीठ की घोषणा के बाद, विधायिका ने धारा 292 में संशोधन किया जो वर्तमान में इस प्रकार है:-

"292. अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री, आदि-

(1) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई अन्य वस्तु, अश्लील मानी जाएगी यदि वह कामुक है या शुद्ध हित के लिए अपील करती है। या यदि इसका प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग आइटम शामिल हैं) तो इसके किसी भी आइटम का प्रभाव, यदि समग्र रूप से लिया जाए, जैसे कि व्यक्ति को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने वाला हो, जो, सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।

(2) जो भी-

(ए) बेचता है, किराये पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाता है, या बिक्री, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या संचलन के प्रयोजनों के लिए कोई अश्लील पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, ड्राइंग, पेंटिंग,

प्रतिनिधित्व या आकृति या कोई भी अन्य अश्लील वस्तु बनाता है, उत्पादन करता है या अपने कब्जे में रखता है, या

(बी) उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण करता है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाई जाएगी, या

(सी) किसी ऐसे व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके दौरान वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई अश्लील वस्तुएं हैं, पूर्वोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए, बनाया, उत्पादित, खरीदा, रखा, आयात, निर्यात, संप्रेषित, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाया गया, या

(डी) विज्ञापन देता है या किसी भी माध्यम से यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, या

(ई) कोई ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा

सकता है। और, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अपवाद.-यह धारा इन तक विस्तारित नहीं है-

(ए) कोई किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनता की भलाई के लिए उचित साबित हो कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या चित्र विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने के हित में है या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुएँ, या

(ii) जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक रूप से रखा या उपयोग किया जाता है;

(बी) कोई मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रतिनिधित्व किया गया प्रतिनिधित्व-

(i) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के अंतर्गत कोई भी प्राचीन स्मारक, या

(ii) किसी भी मंदिर पर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी कार पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी या इस्तेमाल की जाने वाली।

17. शुरुआत में, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की भूमिका, कब्जे की अवधारणा और कैसे कब्जा धारा 292 आईपीसी के तहत कवर नहीं किया गया है, के संबंध में कुछ अधिकारियों से हमारी सराहना की है।' हम उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम केवल व्याख्यात्मक पहलू तक ही सीमित रहेंगे जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। उक्त पहलू की सराहना करने के लिए, आईटी अधिनियम में जगह पाने वाले कुछ प्रावधानों को समझना आवश्यक है और न्यायालय ने इसे कैसे समझा है। इसके अलावा, यह वास्तव में देखा जाना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकलने वाली कोई गतिविधि, जो अश्लील हो सकती है, आईपीसी की धारा 292 या आईटी अधिनियम की धारा 67 या दोनों या आईटी अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत दंडनीय होगी।

18. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन पर, यह विवाद से परे है कि सामग्री का कथित कब्ज़ा आईटी अधिनियम की धारा 2(1)(टी) के तहत परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। शब्दकोश खंड इस प्रकार है:-

> "धारा 2(1)(टी). इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या उत्पन्न डेटा, संग्रहीत छवि या ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त या भेजा गया या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिश;"

इस प्रकार, विचाराधीन अपराध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है।

19. स्लिरेया सिंह अल बनाम भारत संघ5 में, न्यायालय आईटी अधिनियम की धारा 66-ए की संवैधानिक वैधता से निपट रहा था और दो न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त प्रावधान को यह कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया:-

"85. ये दो मामले दर्शाते हैं कि कैसे न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग किसी व्यक्ति को दोषी या गैर-दोषी पाएंगे, जो न्यायाधीश की धारणा पर निर्भर करता है कि "अत्यधिक आक्रामक" या "खतरनाक" क्या है। कोलिन्स मामले में, लीसेस्टरशायर के दोनों न्यायाधीशों और रानी की पीठ के दो न्यायाधीशों ने कोलिन्स को बरी कर दिया होगा जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे दोषी ठहराया था। इसी तरह, चैंबर्स मामले में, क्राउन कोर्ट ने चैंबर्स को दोषी ठहराया होगा जबकि क्वीन्स बेंच ने उन्हें बरी कर दिया। यदि न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग तथ्यों के एक ही सेट पर बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर आ सकते हैं तो यह स्पष्ट है, "बेहद आक्रामक" या "खतरनाक" जैसी अभिव्यक्तियाँ इतनी अस्पष्ट हैं कि ऐसा कोई प्रबंधनीय मानक नहीं है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, धारा 66-ए का एक संभावित अपराधी और धारा 66-ए को लागू करने वाले अधिकारियों के पास बिल्कुल कोई प्रबंधनीय मानक नहीं है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को धारा 66-ए के तहत अपराध के लिए बुक किया जा सके। ऐसा होने पर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उद्धृत दो अंग्रेजी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 66-ए असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट है।

86. अंततः, चिंतामन राव 6 और वी.जी. रो-केस में संदर्भित परीक्षणों को लागू करते हुए, जो पहले निर्णय में संदर्भित थे, यह स्पष्ट है कि धारा 66-ए मनमाने ढंग से, अत्यधिक और असंगत रूप से

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आक्रमण करती है और ऐसे अधिकार और ऐसे अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को बिगाड़ देती है।"

20. इसके बाद न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद राज्य बिहार और केंद्रीय कारागार बनाम राम मनोहर लोहिया9 का हवाला दिया और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:-

"94. ये दो संविधान पीठ के फैसले हमें बांधते हैं और सीधे धारा 66-ए पर लागू होंगे। इसलिए, हम मानते हैं कि यह धारा इस आधार पर भी असंवैधानिक है कि यह अपने दायरे में संरक्षित भाषण और भाषण को लेती है जो प्रकृति में निर्दोष है और इसलिए इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और इसलिए, अतिव्यापकता के आधार पर इसे खत्म करना होगा।"

21. अश्लीलता से निपटने के दौरान, कर्ट ने रंजीत डी. उदेशी (सुप्रा) और अन्य निर्णयों का उल्लेख किया और इस प्रकार राय दी: -

"48. रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस बात पर प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया कि जो कुछ भी पारित किया जाएगा वह अश्लील नहीं होगा। न्यायालय ने हिकलिन केस 10 में पुराने अंग्रेजी फैसले में निर्धारित परीक्षण का पालन किया, जो यह था कि क्या अश्लील के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को अपमानित और भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में इस प्रकार का

प्रकाशन पड़ सकता है। इस निर्णय के बाद से यू.के., संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ हमारे देश में भी काफी प्रगति हुई है। इस प्रकार, दूरदर्शन महानिदेशालय बनाम आनंद पटवर्धन 11 में इस न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून पर ध्यान दिया और कहा कि किसी सामग्री को अश्लील माना जा सकता है यदि समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति को लगे कि समग्र रूप से ली गई विषय-वस्तु विवेकपूर्ण रुचि को आकर्षित करती है और यदि समग्र रूप से ली जाए तो इसमें गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक, शैक्षिक या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव है (पैरा 31 देखें)।

49. इस न्यायालय के हालिया निर्णय, अवीक सरकार बनाम डब्ल्यू.बी.11 राज्य में, इस न्यायालय ने अंग्रेजी, अमेरिकी और कनाडाई निर्णयों का उल्लेख किया और हिकलिन (सुप्रा) परीक्षण से दूर चले गए और समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण लागू किया।

50. सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध को उकसाने के संबंध में जो कहा गया है वह यहां भी समान रूप से लागू होता है। धारा 66-ए को संभवतया ऐसा अपराध बनाने वाला नहीं कहा जा सकता जो "शालीनता" या "नैतिकता" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस धारा के तहत जो बेहद आक्रामक या कष्टप्रद हो सकता है, उसे बिल्कुल भी अश्लील नहीं होना चाहिए-वास्तव में "अश्लील" शब्द धारा 66-ए में अपनी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है।"

22. देवीदास रामक्लिंड्रा तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 13 में उक्त निर्णय का विश्लेषण करते हुए एक अन्य दो-न्यायाधीश पीठ ने राय दी है कि जहां तक अश्लीलता के परीक्षण का सवाल है, प्रचलित परीक्षण समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण है। यहां यह नोट करना उचित है कि उक्त मामले में न्यायालय इस मुद्दे से निपट रहा था कि जब महात्मा गांधी जैसी हस्तियों का उल्लेख किया जाता है तो किस प्रकार का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा:-

> "142. जब महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया जाता है या प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, बोला जाता है या अश्लील शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो "डिग्री" की अवधारणा सामने आती है। विस्तार से कहें तो, "समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण" अधिक जोश के साथ लागू हो जाता है, अधिक मात्रा में और उच्चारित ढंग से। अन्यथा एक ही भाषा के उपयोग के लिए समसामयिक सामुदायिक मानक परीक्षण में क्या उत्तीर्ण हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, यदि महात्मा गांधी के नाम का उपयोग प्रतीक या संकेत या अतियथार्थवादी आवाज के रूप में किया जाता है या उन्हें ऐसे कार्य करते हुए दिखाया जाता है जो अश्लील हैं। इतना निष्कर्ष निकालते हुए, हम इसे कवि पर छोड़ते हैं कि वह अपना बचाव यह बताते हुए करे कि उसने किस तरीके से और किस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया है। हमारी राय केवल यह है कि आईपीसी की धारा 292 के तहत आरोप तय करने के संबंध में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है।"

23. स्लिरेया सिंगलल (सुप्रा) का संदर्भ केवल यह दिखाने के लिए है कि उक्त मामले में न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66-ए की संवैधानिक वैधता से निपटने के दौरान देखा कि उक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से "अश्लील" शब्द नहीं था। उसने उस संबंध में और कुछ नहीं कहा. मौजूदा मामले में यह देखना जरूरी है कि किसी आरोपी पर किस प्रावधान या दोनों के तहत मुकदमा चलाया जाना जरूरी है। हमने वर्तमान अवतार में आईपीसी की धारा 292 को पहले ही पुन: प्रस्तुत कर दिया है। आईटी अधिनियम की धारा 67 जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा का प्रावधान करती है, इस प्रकार है: -

> "67. इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा। - जो कोई भी किसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित कराता है, जो कामुक है या शुद्ध हित को आकर्षित करता है या यदि उसका प्रभाव ऐसा है कि वह भ्रष्ट और भ्रष्ट व्यक्तियों की ओर प्रवृत्त होता है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं, पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी या उसके बाद की सजा की स्थिति में पांच साल तक की कैद और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।"

24. धारा 67 ए इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 67बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में

बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार है:-

"67 बी. इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कार्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा। - जो कोई -

(ए) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित या प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है जो स्पष्ट यौन कार्य या आचरण में लगे बच्चों को दर्शाता है; या

(बी) पाठ या डिजिटल छवियां बनाता है, बच्चों को अश्लील या अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापन करता है, प्रचार करता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है; या

(सी) स्पष्ट यौन कृत्य के लिए या इस तरीके से बच्चों को एक या एक से अधिक बच्चों के साथ ऑनलाइन संबंध बनाने के लिए प्रेरित, प्रलोभित या प्रेरित करता है जिससे कंप्यूटर संसाधनों पर एक उचित वयस्क को ठेस पहुंच सकती है; या

(डी) बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की सुविधा प्रदान करता है; या

(ई) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में खुद के दुर्व्यवहार या बच्चों के साथ स्पष्ट यौन कृत्य से संबंधित दूसरों के रिकॉर्ड, पहली बार दोषी पाए

जाने पर किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में सात साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है, जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है:

बशर्ते कि धारा 67, धारा 67 ए और इस धारा के प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व या आकृति तक विस्तारित नहीं हैं-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनता की भलाई के लिए उचित साबित हो कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने या अन्य सामान्य चिंता की वस्तुएँ के हित में है; या बी (ii) जो प्रामाणिक विरासत या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या उपयोग किया जाता है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए "बच्चों" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

25. आईटी अधिनियम की धारा 69 किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। जितना यह कहा गया है इसमें एक दंडात्मक तथ्य भी शामिल है, जो ग्राहक या मध्यस्थ उप-धारा (3) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

26. हमने आईटी अधिनियम के इन सभी प्रावधानों का उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि विधायिका ने जानबूझकर "इलेक्ट्रॉनिक रूप" शब्दों का उपयोग किया है। डॉ. सिंघवी ने हमारे ध्यान में आईटी अधिनियम की धारा 79 लायी है जो अध्याय XII में आती है जो कुछ मामलों में उत्तरदायी नहीं होने वाले मध्यस्थों से संबंधित है। विद्वान वकील ने श्रेया सिंघल (सुप्रा) पर भी भरोसा किया है कि अदालत ने आईटी अधिनियम की धारा 79 को चुनौती से कैसे निपटा है। न्यायालय ने उक्त प्रावधान को छूट और धारा 69ए के साथ जोड़ा है और उस संदर्भ में व्यक्त किया है कि:-

> "121. सबसे पहले इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि धारा 79 एक छूट प्रावधान है। छूट प्रावधान होने के नाते, यह उन प्रावधानों से निकटता से संबंधित है जो धारा 69-ए सहित अपराधों के लिए प्रावधान करते हैं। हमने देखा है कि कैसे धारा 69-ए के तहत प्रवर्तक और मध्यस्थ की सुनवाई सहित कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश द्वारा ही अवरोधन किया जा सकता है। हमने यह भी देखा है कि कैसे केवल दो तरीके हैं जिनसे कोई अवरोध आदेश पारित किया जा सकता है - एक 2009 के नियमों का अनुपालन करने के बाद नामित अधिकारी द्वारा और दूसरा नामित अधिकारी द्वारा जब उसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करना होता है। सूचना को अवरुद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपना दिमाग लगाने वाला मध्यस्थ 2009 के नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 69-ए में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

122. धारा 79(3)(बी) को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि मध्यस्थ को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर, एक अदालती आदेश पारित किया गया है जिसमें उसे कुछ सामग्री को शीघ्रता से हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए कहा गया है, फिर उस सामग्री को शीघ्रता से हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने में विफल होना चाहिए। ऐसा इस कारण से है कि अन्यथा Google, Facebook इत्यादि जैसे मध्यस्थों के लिए कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होगा जब लाखों अनुरोध किए जाएंगे और मध्यस्थ को यह निर्णय करना होगा कि ऐसे अनुरोधों में से कौन सा वैध है और कौन सा नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि दुनिया भर के अन्य देशों में इस दृष्टिकोण को स्वीकृति मिल गई है, अर्जेंटीना सबसे आगे है। साथ ही, न्यायालय के आदेश और/या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित विषय-वस्तुओं के अनुरूप सख्ती से पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित से परे गैरकानूनी कार्य स्पष्ट रूप से धारा 79 का कोई हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इन दो चेतावनियों के साथ, हम धारा 79(3)(बी) को रद्द करने से बचते हैं।

123. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि दुनिया भर में बिचौलियों के लिए उपयोगकर्ता अनुबंध रखना एक आम बात है जिसमें नियम 3(2) में बताई गई बातें शामिल हैं। हालाँकि, नियम 3(4) को धारा 79(3)(बी) की तरह ही पढ़ने की आवश्यकता है। उक्त उप-नियम में बताया गया ज्ञान केवल अदालती

आदेश के माध्यम से होना चाहिए। इसके अधीन, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 वैध हैं।"

27. हमने उपरोक्त पहलू का उल्लेख किया है क्योंकि डॉ. सिंघवी द्वारा तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता को उक्त प्रावधान के तहत संरक्षित किया गया है, भले ही पूरे आरोप स्वीकार कर लिए जाएं। उनके अनुसार, एक बार जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 वास्तव में आईपीएसओ और आईपीएसओ ज्यूर पर लागू होनी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने धारा 79 का आग्रह किया है, जैसा कि भाषा सुझाती है और इंटरनेट की दुनिया के प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए जहां प्लेटफार्मों के सेवा प्रदाता नियंत्रण नहीं करते हैं और वास्तव में ऐसे इंटरनेट प्लेटफार्मों के प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उपयोगकर्ताओं के कृत्यों/चूक को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, मध्यस्थ की तब तक रक्षा करता है जब तक उसे वास्तविक ज्ञान न हो जाए। उनका तर्क है कि अधिनियम ने आईटी अधिनियम के तहत धारा 2(1)(जेड)(ए) के संदर्भ में 'प्रवर्तक' नामक एक अलग और विशिष्ट श्रेणी बनाई है, जिसे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षा जानबूझकर नहीं दी गई है। Shreya Singhal (सुप्रा) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, उन्होंने आग्रह किया है कि क्षितिज का विस्तार किया गया है और आईटी अधिनियम की धारा 79 का प्रभाव व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, चूंकि प्रावधान को वास्तविक ज्ञान की अवधारणा पर जोर देते हुए पढ़ा गया है। उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, उनके द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 79 स्वचालित रूप से मध्यस्थों द्वारा प्रकाशन और प्रसारण के इलेक्ट्रॉनिक रूपों की ओर आकर्षित हो जाती है, चूँकि यह स्पष्ट रूप से गैर-अस्थिर खंडों का उपयोग करता है और लागू किसी भी अन्य कानून पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, तीन प्रावधानों पर

जोर दिया गया है, अर्थात् धारा 67, 79 और 81, और डॉ. सिंघवी के अनुसार, तीन प्रावधान एक समग्र त्रिमूर्ति का गठन करते हैं। इस संबंध में, हम आईटी अधिनियम की धारा 81 को पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:-

> "81. अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव होना.- इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।
>
> बशर्ते कि इस अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट अधिनियम 1957 या पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।"

यह प्रावधान 2009 के अधिनियम 10 द्वारा 27.10.2009 से जोड़ा गया है।

28. प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, यह दोहराना होगा कि धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने, प्रसारित करने के लिए स्पष्ट रूप से सजा निर्धारित करती है। धारा 67 ए और 678 के साथ पठित उक्त प्रावधान आईटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित एक पूर्ण संहिता है। धारा 79, जैसा कि व्याख्या की गई है, व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक छूट प्रावधान है। हालाँकि, उक्त सुरक्षा का विस्तार श्रेया सिंघल (सुप्रा) के आदेश में किया गया है और हम इससे सहमत हैं। धारा 81 जी में यह भी विशेष रूप से प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। यदि कथित अपराध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अपराध से संबंधित है, तो सभी प्रावधानों का अपना महत्व और महत्व होगा। यह ध्यान में रखना होगा कि आईटी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। इसमें विशेष प्रावधान हैं.

आईपीसी की धारा 292 अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि को अपराध बनाती है, लेकिन एक बार जब अपराध का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंध या संबंध हो जाता है तो धारा 79 के संरक्षण और प्रभाव को नजरअंदाज या नकारा नहीं जा सकता है। हम ऐसा सोचने के इच्छुक हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है और अधिनियम को प्रभावी बनाया जाना है ताकि संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके और विधायी मंशा के अनुरूप बनाया जा सके। आईटी अधिनियम की धारा 81 के पीछे यही आदेश है। आईटी अधिनियम द्वारा दी गई अतिरिक्त सुरक्षा लागू होगी। इस संबंध में, हम श्रावम सिंह और अन्य बनाम कस्तूरीलाल 14 का उल्लेख कर सकते हैं। न्यायालय स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956 की धारा 39 पर विचार कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि उक्त अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में गैर-अस्थिर खंड भी शामिल थे। उसी की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा:-

> "जब दो या दो से अधिक कानून एक ही क्षेत्र में संचालित होते हैं और प्रत्येक में एक गैर-अस्थिर खंड होता है जिसमें कहा जाता है कि इसके प्रावधान किसी अन्य कानून से आगे निकल जाएंगे, तो व्याख्या की उत्तेजक और गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि वैधानिक व्याख्या में कोई पारंपरिक प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए ऐसे संघर्ष के मामलों का निर्णय विचाराधीन कानूनों के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए। एक विकट स्थिति, हमारे सामने जैसा मामला, श्री राम नारायण बनाम शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड में सामने आया था। प्रतिस्पर्धी कानून बैंकिंग कंपनी

अधिनियम, 1949, 1953 के अधिनियम 52 द्वारा संशोधित, और विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 हैं। . बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 45-ए, जिसे 1953 के संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, और विस्थापित व्यक्ति अधिनियम, 1951 की धारा 3 में प्रत्येक में एक गैर-अस्थिर खंड शामिल था, जो प्रदान करता था कि कुछ प्रावधानों का प्रभाव "तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद होगा...।" इस न्यायालय ने दो कानूनों के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करके और बैंकिंग कंपनी अधिनियम को प्राथमिकता देते हुए विवाद का समाधान किया:

"इसलिए, किसी दिए गए मामले में, इन दोनों अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति के व्यापक विचारों पर, इन दोनों अधिनियमों में एक या दूसरे प्रासंगिक प्रावधानों के अधिभावी प्रभाव को निर्धारित करना वांछनीय है और उसमें प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा द्वारा स्पष्ट इरादा बताया गया है" (पृष्ठ 615)

जैसा कि हमने संकेत दिया है, विशेष और विशिष्ट उद्देश्य जिसने दिल्ली किराया अधिनियम की धारा 14-ए और अध्याय IIIA के अधिनियमन को प्रेरित किया, वह पूरी तरह से विफल हो जाएगा यदि स्लम क्लीयरेंस अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता वाले प्रावधान उन पर हावी हो गए। इसलिए, दिल्ली किराया अधिनियम के नए शुरू किए गए प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए और स्लम क्लीयरेंस अधिनियम में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद इसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।"

29. तालचेर नगर पालिका बनाम तालचेर विनियमित बाजार समिति16 में, न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 या उड़ीसा कृषि उपज, बाजार अधिनियम, 1956 लागू होना चाहिए। 1956 अधिनियम की धारा 4(4) में एक गैर-प्रतिरोधी खंड शामिल था। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा:-

> "हालाँकि, अधिनियम में विशेष प्रावधान शामिल हैं। उक्त अधिनियम की धारा 4(4) का प्रावधान किसी भी मौजूदा कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद लागू होता है। उक्त अधिनियम के प्रावधान, इसलिए, उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होगा। इस प्रकार, कहावत "जेनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डिरोगेंट" इस मामले में लागू होगी। (डी.आर. यादव बनाम आर.के. सिंहर, भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम बनाम भारत संघ 18 और म.प्र. विद्युत कर्मचारी संघ बनाम म.प्र. विद्युत बोर्ड 19 देखें।)"

30. राम नारायण (सुप्रा) में, न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां दोनों क़ानून, अर्थात् बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 और विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 में गैर-अस्थिर खंड शामिल थे। न्यायालय ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम को प्रधानता दी। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत विकसित किया: -

> "7 .... इसलिए, किसी दिए गए मामले में, इन दोनों अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति के व्यापक विचारों पर, इन दोनों अधिनियमों में एक या दूसरे प्रासंगिक प्रावधानों के अधिभावी प्रभाव

को निर्धारित करना वांछनीय है और उसमें प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा द्वारा स्पष्ट इरादा व्यक्त किया गया है।"

31. सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम फेयरग्रोट/1 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, यह न्यायालय दो विशेष क़ानूनों से निपटते समय, अर्थात्, विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 की धारा 13 और बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 32, इस प्रकार देखी गई: -

"जहां दो विशेष क़ानून हैं जिनमें गैर-अस्थिर खंड शामिल हैं, बाद के क़ानून को प्रभावी होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद के क़ानून के अधिनियमन के समय, विधानमंडल को पहले के कानून और उसके गैर-अस्थिर खंड के बारे में पता था। यदि विधायिका अभी भी बाद के अधिनियम को एक गैर-अस्थिर खंड प्रदान करती है तो इसका मतलब है कि विधायिका चाहती थी कि वह अधिनियम कायम रहे। यदि विधानमंडल नहीं चाहता कि बाद का अधिनियम लागू रहे तो वह बाद के अधिनियम में यह प्रावधान कर सकता है और करेगा कि पहले के अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे।"

32. उपरोक्त परिच्छेद स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि विधायी मंशा स्पष्ट है कि बाद वाला अधिनियम लागू होगा तो इसकी व्याख्या उक्त मंशा के अनुसार की जाएगी: हम पहले ही आईटी अधिनियम की योजना का उल्लेख कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अश्लीलता अधिनियम की योजना के अंतर्गत आती है। हमने आईटी अधिनियम की धारा 79 और 81 का भी उल्लेख किया है। एक बार जब अधिभावी

प्रभाव वाले विशेष प्रावधान किसी आपराधिक कृत्य और अपराधी को कवर कर लेते हैं, तो वह आईपीसी और इस मामले में, धारा 292 के दायरे से बाहर हो जाता है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि ट्रांसमिशन के इलेक्ट्रॉनिक रूप आईटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो एक विशेष कानून है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि एक विशेष कानून सामान्य और पूर्व कानूनों पर हावी होगा। जब अधिनियम विभिन्न प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता से संबंधित है, तो यह आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध को कवर करता है।

33. जीवन कुमार राउल बनाम सीबीपी' में, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (टीओएचओ) के संदर्भ में इसे एक विशेष कानून मानते हुए, न्यायालय ने कहा:-

> "22. TOHO एक विशेष क़ानून है, संहिता की धारा 4, जो आमतौर पर संज्ञेय अपराध की जांच या अन्य प्रावधानों के लिए लागू होती है, लागू नहीं हो सकती है। धारा 4 में जांच, पूछताछ, परीक्षण आदि का प्रावधान है। संहिता के प्रावधानों के अनुसार. हालाँकि, धारा 4 की उपधारा (2) विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि किसी भी अन्य कानून के तहत अपराधों की जांच, पूछताछ, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ, मुकदमा चलाने या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी समय लागू अधिनियम के अधीन।'

23. TOHO एक विशेष अधिनियम है और उसके तहत अपराधों से निपटने से संबंधित मामला उसके प्रावधानों के कारण विनियमित किया गया है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है कि यह संहिता के प्रावधानों पर लागू होगा।

और फिर:-

> "27. इस प्रकार, संहिता के प्रावधान, सभी इरादों और अभिप्रायों के लिए, केवल एक हद तक लागू होंगे जब तक कि संहिता और टीओएचओ के प्रावधानों के बीच संघर्ष उत्पन्न न हो जाए और जैसे ही संघर्ष का क्षेत्र पहुंच जाए, तो टीओएचओ संहिता पर हावी हो जाएगा। सामान्यतः, इस प्रकार, यद्यपि संहिता के संदर्भ में, जांच पूरी होने पर और समय-समय पर आरोपी की रिमांड प्राप्त करने पर प्रतिवादी को पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती थी, टीओएचओ की धारा 22 में निहित प्रावधानों के कारण उसे ऐसा करने से रोक दिया गया था।"

34. उपरोक्त विश्लेषण और यहां उल्लिखित प्राधिकारियों के मद्देनजर, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया है कि यद्यपि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप नहीं लगाया गया है, फिर भी अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

35. नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया जाता है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है।)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।